

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2655/2024

जगदीश सिंह राजपुरोहित

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता (गुणवता एवं नियंत्रण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त बालोतरा।

—प्रत्यर्थांगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.08.2024

आदेश की दिनांक : 06.11.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थांगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 07.05.2024 को

अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को पूर्व की भांति कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता कार्यालय खंड, बालोतरा, बाडमेर हाल ही निलंबित कार्यालय शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा सीसीए नियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबित किया गया, जो नियम विरुद्ध है। उनका तर्क है कि परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के अंतर्गत निलंबन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलंबन की पुष्टि का प्रकरण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा और विलम्ब होने पर समुचित कारण अंकित किया जायेगा तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा निलंबन आदेश की पुष्टि के बाद 45 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। परंतु अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया निलंबन आदेश जिसे 3 माह से अधिक का समय हो चुका है लेकिन आज दिनांक तक अपीलार्थी को आरोप पत्र नहीं दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 1912/2015 एसएलपी संख्या 31761/2013 अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि निलंबन आदेश की निरंतरता को 3 माह से अधिक विस्तारित नहीं की जानी चाहिये जब तक की उसे 3 माह के अंदर आरोप पत्र तामील नहीं करा दिया जाये। परंतु वर्तमान मामले में 3 माह से अधिक का समय बीत चुका है और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया जो उक्त नियम एवं विधि के विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 07.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को पूर्व की भांति कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा बढ़ती गई गंभीर अनियमितताओं के लिये उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण

एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचारण में होने के कारण से नियम 13(1)(क) के अंतर्गत आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा निलंबित किया गया, जिसमें किसी नियमों का उल्लंघन नहीं है और सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है। विभाग के परिपत्रानुसार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव अपीलार्थी के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त हो जाने के उपरांत कमी पूर्ति के लिये कार्मिक विभाग के स्तर पर परीक्षाधीन है और इस प्रकार अपीलार्थी को निलंबन से बहाली के विषय को स्वतः निर्णीत नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता कार्यालय खंड, बालोतरा, बाडमेर हाल ही निलंबित कार्यालय शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा सीसीए नियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबित किया गया। परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के अंतर्गत निलंबन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलंबन की पुष्टि का प्रकरण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा और विलम्ब होने पर समुचित कारण अंकित किया जायेगा तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा निलंबन आदेश की पुष्टि के बाद 45 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। परंतु अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया निलंबन आदेश जिसे 3 माह से अधिक का समय हो चुका है लेकिन आज दिनांक तक अपीलार्थी को आरोप पत्र नहीं दिया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह तक आरोप पत्र नहीं दिये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश के संबंध में आरोप पत्र दिया जा चुका है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है और अधिकरण के समक्ष बहस के दौरान तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है, जो लगभग 3 माह से अधिक अवधि उपरांत भी अपीलार्थी को आरोप पत्र नहीं दिया

गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us.

So far as the facts of the present case are concerned, the Appellant has now been served with a Chargesheet, and, therefore, these directions may not be relevant to him any longer. However, if the Appellant is so advised he may challenge his continued suspension in any manner known to law, and this action of the Respondents will be subject to judicial review."

इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विरुद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 07.05.2024 को उक्त न्यायिक विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुये अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी का नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग स्वतंत्र है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष